(ग) अप्रैल-दिसम्बर, 96 की अवधि के दौरान, जबकि सूती हथकरघा फैब्रिक्स के निर्यात में कमी हुई है, सूती हथकरघा मदों के निर्यातों में वृद्धि हुई है। तथापि, अप्रैल-दिसंबर, 96 की अवधि के दौरान सूती हथकरघा फैब्रिक्स तथा मेड-अप्स के संपूर्ण निर्यातों में वर्ष 1995 की इसी अवधि के दौरान किए गए निर्यातों पर 7% की वृद्धि दर्ज की गई है।

(घ) अप्रैल-दिसम्बर, 96 की अवधि के दौरान तथा वर्ष 1995 की इसी अवधि में सूती हथकरघा फैब्रिक्स तथा मेड-अप्स के निर्यात निम्न प्रकार हैं:—

(फैब्रिक्स वर्ग मी०) (मेड-अप्स कि० ग्रा० में) (आंकड़े 000, में)

अवधि	फैब्रिक्स		मेड-अप्स	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
अप्रैल,-दिसंबर, 95	43661	191434	54596	8719970
अप्रैल-दिसंबर, 96	35703	1732124	60316	9676879

(ङ) हथकरघा क्षेत्र में वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान कपड़े का कुल उत्पादन निम्न प्रकार है:—

वर्ष	उत्पादन (मिलियन वर्ग० मी० में)
1993-94	5851
1994-95	6180
1995-96	7020

कपड़ा मिल क्षेत्र में उत्पादन में कमी

1301. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में जहां कपड़ा उत्पादन के कार्य में कपड़ा मिल क्षेत्र में कमी हुई है वहीं पावरलूम व हथकरघा क्षेत्र में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कपड़ा मिल क्षेत्र, पावरलूम क्षेत्र और हथकरघा क्षेत्र में वर्ष 1990-91 तथा वर्ष 1995-96 के दौरान कितना-कितना कपड़ा उत्पादन किया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा इस अवधि के दौरान कपड़ा उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में अनेक आर्थिक एवं प्रशासनिक प्रोत्साहन दिए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहनों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा): (क) (i) संगठित सूती/मानव-निर्मित फाईबर वस्त्र मिल क्षेत्र वस्त्र मदों अर्थात स्पन यार्न तथा कपड़े के उत्पादन में लगा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, स्पन यार्न के उत्पादन में वृद्धि हुई, जबकि इस क्षेत्र में कपड़े के उत्पादन में कमी हुई है।

(ii) हथकरघा तथा विद्युतकरघा क्षेत्र केवल कपड़े के उत्पादन में लगे हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन दोनों क्षेत्रों में कपड़े का उत्पादन बढ़ा है।

(ख) वर्ष 1990-91 तथा 1995-96 के दौरान वस्त्र मिल विद्युतकरघा तथा हथकरघा क्षेत्र में वस्त्रों के कुल उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

	क्षेत्र	मद	1990-91	1995-96
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सूती / मानव निर्मित फाईबर	यार्न (मि०कि०ग्रा०)	1824	2273
2.	वस्त्र मिल क्षेत्र	कपड़ा (मि०मि०)	2589	2019
3.	विद्युत करघा क्षेत्र	कपड़ा (मि० वर्ग मी०)	13340	7050
4.	हथकरघा	कपड़ा (मि०वर्ग मी०)	4295	7020

(ग) और (घ) भारतीय वस्त्र उद्योग में विविध क्षेत्र शामिल हैं नामतः मिल क्षेत्र विद्युतकरघा, हथकरघा आदि। उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए नीति परक हस्तक्षेप, जिसमें वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रोत्साहनों का निर्धारण करना शामिल है / उपाय किए जाते हैं जो कि वर्ष 1985 की वस्त्र नीति में निर्धारित व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं तथा यह एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में वस्त्र उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए समय-समय पर विविध कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:—

मिल क्षेत्र: रुग्ण औद्योगिक एककों के कार्यचालन की जांच करने के लिए बी आई एफ आर की स्थापना करना तथा मिलों के पुनरुद्धार के लिए यथोचित योजनाओं को तैयार तथा स्वीकृत करना, लाइसेंसिंग प्रावधानों का उदारीकरण करना, वित्तीय पुर्नसंरचना करना, ओ जी एल के अंतर्गत वस्त्र मशीनरी के आयात की अनुमति देना तथा ऐसे आयातों पर सीमा शुल्क को कम करना, अनुसंधान तथा विकास करना आदि।

विद्युत करघा: विद्युतकरघा सेवा केन्द्र, कम्प्यूटर सहायित डिजाइन (सी ए डी) केन्द्रों को चलाना तथा विद्युतकरघा विकास तथा निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना करना।

हथकरघा: हैंक यार्न दायित्व योजना के कार्यान्वयन के द्वारा हथकरघा क्षेत्र को यार्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, केवल हथकरघा क्षेत्र द्वारा ही विनिर्माण के लिए कुछ मदों का आरक्षण करना, प्लेन रील में सूती तथा सेलूलोसिक स्पन यार्न को शुल्क की पूर्णतया छूट देना, हथकरघा सहकारी समितियों (एच सी एस) द्वारा क्रोस रील हैंक यार्न की खरीद के मामले में शुल्क की रियायती दर की अनुमति देना, पंजीकृत एच सी एस द्वारा विस्कोस फिलामेंट यार्न की खरीद के लिए शुल्क की रियायती दर की अनुमति देना, एच सी एस के स्वामित्व वाली फैक्ट्री द्वारा प्रसंस्कृत हथकरघा क्षेत्र के सूती फैब्रिकों को शुल्क से छूट देना, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र प्रसंस्करण कर्ताओं द्वारा प्रसंस्कृत हथकरघा फैब्रिक्स के मामले में शुल्क की रियायती दर की अनुमति देना, एस सी एस द्वारा प्रसंस्कृत हथकरघा तथा ऊनी फैब्रिक को शुल्क से छूट देना, तथा एस सी एस को अपरिष्कृत ऊन के आयात के लिए शुल्क से छूट देना।

कपास निर्यात का लक्ष्य

1302. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1995-96 के लिए कपास के निर्यात के लिए एक मात्रा निर्धारित की थी;

(ख) यदि हां, तो वह मात्रा कितनी थी और क्या कपास का निर्यात निर्धारित लक्ष्यानुसार दिया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो निर्यात की मात्रा कितनी थी और निर्धारित लक्ष्यानुसार निर्यात न हो पाने के क्या कारण थे;

(घ) क्या सरकार कपास के निर्यात को प्रतिबंधित मदों की सूची से हटाकर इसे स्वतंत्र करने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा): क) सरकार ने कपास के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। तथापि, सरकार कपास के उत्पादन के